

# VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

B

Test Booklet Code: 419

Test Booklet No: 580081

Total Ques: 100

- 1 C  
Ex. To protect monuments and places of public importance is not mentioned under Article 51A of the Indian Constitution.
- 2 B  
Ex. To foster respect for international law : Article 51 (c)  
To have compassion for living creatures : Article 51A (g)  
To develop spirit of inquiry and reform : Article 51-A (h)  
To separate judiciary from the executive in Public Service of the State : Article 50
- 3 D  
Ex.
- 4 B  
Ex. The Ministries/Departments of the Government of India are not created by Prime Minister on the recommendation of Cabinet Secretary. Cabinet Secretary is the head of Cabinet Secretariat. He is also the chairman of the Civil Services Board. Each of the Ministries is assigned to a Minister by the President of India on the advice of the Prime Minister. Hence, statement (1) is incorrect, and statement (2) is correct.
- 5 D  
Ex.
- 6 D  
Ex. Advocate General : Appointed by Governor, not President.  
High Courts : Have original and appellate jurisdiction, but no advisory jurisdiction under CPC.
- 7 A  
Ex.
- 8 A  
Ex.
- 9 D  
Ex. According to Article 108 of the Constitution, a joint session of both the Houses is called to discuss on such a Bill on which both the Houses have a different opinion. Joint Session is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
- 10 C  
Ex.
- 11 A  
Ex.
- 12 B  
Ex. A Vote-on-Account is the expenditure outlay for the functioning of the government presented by the Finance Minister to the Parliament seeking approval for the estimated expenses to be incurred in the next few months. While vote-on-account is sometimes referred to as Interim Budget. Interim Budget is more than presenting the expenditure; it also provides the receipt estimates along with the estimated expenditure.
- 13 D  
Ex.
- 14 B  
Ex.

- 15 A  
Ex. The writ of Certiorari is issued to a lower court directing that the record of a particular case be sent up for review, together with all supporting files, evidence and documents, usually with the intention of overruling the judgment of the lower Court. It is one of the mechanisms by which the Fundamental Rights of the citizens are protected.
- 16 B  
Ex.
- 17 A  
Ex.
- 18 C  
Ex.
- 19 B  
Ex. The National Development Council was established in August, 1952. It consists of the following members- (1) Prime Minister as its Chairman, (2) Ministers of the Union Cabinet, (3) Chief Ministers of all the states, (4) Chief Minister/Administrators of the Union Territories, (5) Members of the Planning Commission.
- 20 D  
Ex.
- 21 B  
Ex. Statement (1) True : State = laws; Society = norms.  
Statement (2) True : Sovereignty = supreme authority, independent of external control.  
Statement (3) False : Sovereignty strengthens, not limits, the state's power.
- 22 B  
Ex.
- 23 C  
Ex. Statement (1) True : Constitution provides basic rules for coordination.  
Statement (2) False : India is secular, no common religion.  
Statement (3) True : Constitution limits government powers.  
Statement (4) True : Preamble expresses aspirations of people.
- 24 D  
Ex.
- 25 B  
Ex. Statement 1 is correct : Constitutionalism ensures that the government operates within the constraints set by the Constitution, meaning that all government actions must comply with the law, preventing arbitrary use of power.  
Statement 3 is correct: Promoting the separation of powers is a key feature of Constitutionalism, ensuring that legislative, executive, and judicial branches function independently and provide checks and balances on each other.
- 26 C  
Ex. The terms in the Preamble to the Indian Constitution appear in the following order: Sovereign, Socialist, Secular, Democratic and Republic.  
Thus, the correct order of the given terms is 3-1-2-4; making option (c) the correct answer.
- 27 A  
Ex.







- 1 C  
Ex. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए के तहत मौलिक कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना खंड (जी) में, राष्ट्रगान का आदर करना खंड (ए) में तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना खंड (1) में शामिल है। 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना' मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में शामिल है।
- 2 B  
Ex. अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना : अनुच्छेद 51(ग) प्राणियों के प्रति दया भाव रखना : अनुच्छेद 51-क(छ) ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास : अनुच्छेद 51-क(ज) राज्य की लोकसेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना : अनुच्छेद 50
- 3 D  
Ex. B
- 4 B  
Ex. D
- 5 D  
Ex. D
- 6 D  
Ex. संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है न कि राष्ट्रपति द्वारा अतः कथन 1 गलत है। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, मूल तथा अपीलीय होती है।
- 7 A  
Ex. A
- 8 A  
Ex. D
- 9 D  
Ex. C
- 10 C  
Ex. A
- 11 A  
Ex. भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से मुद्रा निकालने के लिए विनियोजन विधेयक पारित करना पड़ता है। अनुपूरक अनुदानों और लेखानुदान तथा संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करके भी लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है।
- 12 B  
Ex. D
- 13 D  
Ex. B
- 14 B  
Ex.

- 15 A  
Ex. एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है, तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रिट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है।
- 16 B  
Ex. A
- 17 A  
Ex. संविधान के अनुच्छेद 256 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा, जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो।
- 18 C  
Ex. B
- 19 B  
Ex. राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त, 1952 में किया गया एवं इसकी रचना में निम्नलिखित सदस्यों का प्रावधान किया गया:  
1. प्रधानमंत्री (इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में)  
2. संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रिगण,  
3. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री  
4. सभी केंद्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्री/प्रशासक, तथा  
5. योजना आयोग के सदस्य।
- 20 D  
Ex. संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधानित है कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। साथ ही अनुच्छेद 325 के अनुसार, प्रत्येक प्रादेशिक (क्षेत्रीय) निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक सूची होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। इससे अतिरिक्त भारत में राजनीतिक दल अपने मानक स्वयं निर्धारित कर सकते हैं।
- 21 B  
Ex. B
- 22 B  
Ex. C
- 23 C  
Ex. D
- 24 D  
Ex.





